eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

एनईपी 2020 का ग्रामीण भारत पर प्रभाव

डॉ स्मिता सिंह[1]

[1]सहयुक्त आचार्य शिक्षाशास्त्र, महिला महाविद्यालय बस्ती, उ0प्र0

Received: 20 July 2025 Accepted & Reviewed: 25 July 2025, Published: 31 July 2025

Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसका उद्देश्य समावेशी, बहु–विषयी, लचीली और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना है। यह नीति विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहां शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और अधोसंरचना जैसी समस्याएं लंबे समय से विद्यमान हैं। एनईपी 2020 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, और व्यावसायिक शिक्षा जैसे कई पहलुओं पर ध्यान दिया है, जिनका सीधा लाभ ग्रामीण छात्रों और समुदायों को मिल सकता है। यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस शोध पत्र में एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए यह आकलन किया गया है कि यह नीति ग्रामीण भारत के शैक्षिक परिदृश्य को कैसे रूपांतरित कर सकती है।

मुख्य शब्द– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ग्रामीण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूली अधोसंरचना

Introduction

नई शिक्षा नीति 2020 का ग्रामीण भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को अक्सर निवेश के बजाय लागत के रूप में देखा जाता है। वे चाहते हैं कि बच्चे कड़ी मेहनत करें और पैसे कमाएँ। यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने, छात्रों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने पर केंद्रित है। जब भी उच्च शिक्षा की बात आती है, तो आस–पास उपयुक्त कॉलेजों की कमी छात्रों को शहरों में स्थानांतरित के लिए मजबूर करती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 कुल 5 स्तंभों पर आधारित है और ये पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही पर दृष्टि रखती है। भारतीय गाँवों में बेरोज़गारी, अशिक्षा, अंधकार, पानी, बिजली, आवास, अंधविश्वास, सड़क, सिंचाई आदि–आदि कई समस्यायें किसी से छुपी नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के तहत शिक्षा को अधिक समग्र और व्यापक बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि कला, संगीत, खेल, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। उद्योग धंधों की कमी के कारण, गाँव के लोग रोज़गार के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत के परिचायक भी हैं। भारतीय समाज के केंद्र, इन्हीं ग्रामवासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चत करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, खेल के मैदान और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच में सुधार करने और छात्रों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराने में मदद करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है, जिसमें वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे भी शामिल हैं। इसके लिए, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों से लैस करने के प्रयास किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, खासकर प्रारंभिक वर्षों में। यह ग्रामीण छात्रों को अपनी भाषा में सीखने और समझने में मदद करेगा, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। यह ग्रामीण छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है।

ग्रामीण विकास भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक सुधार का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के पाँच तत्वों की पहचान की गई, ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कें. जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक परिवर्तन लाना। इसमें आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण सहित कई पहलू शामिल हैं। ग्रामीण विकास से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास के मुख्य पहलू में आर्थिक विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण, के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण, सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं, डिजिटल विभाजन, सामुदायिक भागीदारी, लैंगिक समानता, प्रौद्योगिकी का उपयोग,वित्तीय सहायता बुनियादी ढांचे का विकास, योग्य शिक्षकों की कमी, आर्थिक बाधाएं इत्यादी अनेक समस्याएं भी है जो सभी स्थानों, वर्गो के समानुपातिक है. है। शिक्षा, उद्यमिता , भौतिक संरचना और सामाजिक संरचना सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी ग्रामीण विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों, और निजी क्षेत्र के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जिसके हल को ढूँढने में यह नई शिक्षा नीति 2020 सहायक होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार और अन्य संगठन विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, और ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

को बढ़ाने के लिए, सरकार स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करती है, और छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करती है। शिक्षा ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन जीने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, सरकार अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करती है, और डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित करती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार ग्रामीण लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार सड़कों, पुलों, बिजली, और पानी जैसी सुविधाओं का निर्माण करती है। बुनियादी ढांचे में सुधार ग्रामीण लोगों के जीवन को आसान बनाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना है। इन कार्यक्रमों में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, और खाद्य सहायता शामिल हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम ग्रामीण लोगों को गरीबी और अभाव से बचाने में मदद करते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं –

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)– यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देता है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)– यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उनकी आजीविका को बढ़ावा देता है।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)– यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करती है ताकि कनेक्टिविटी में सुधार हो सके।

4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)– यह कार्यक्रम बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को सामाजिक सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एक बड़ी चुनौती है, और इससे निपटने के लिए व्यापक प्रयास की आवश्यकता है, साथ ही बेरोजगारी एक और बड़ी चुनौती है, और इसके लिए रोजगार के अवसरों को ग्रामीण अंचल में बढ़ाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक चुनौती है, और इसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी एक अलग चुनौती है, और इसे बेहतर बनाये बिना नई शिक्षा नीति 2020 अपने स्वरुप को प्राप्त करने में किस प्रकार से सक्षम होगी यह भी किसी चुनौती से कम नहीं होगी।भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) ने ग्रामीण भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम में बदलाव, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर। नई शिक्षा नीति 2020 ग्रामीण भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। यह शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समावेशिता में सुधार करके ग्रामीण छात्रों को सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, शहरी क्षेत्रों की तुलना में, कई चुनौतियों का सामना करती है, जिनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी, योग्य शिक्षकों की कमी, और आर्थिक और सामाजिक बाधाएं शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, शिक्षा ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण शिक्षा की चुनौतियां–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

1. ग्रामीण स्कूलों में अक्सर कक्षाएं, फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, जिससे छात्रों के लिए प्रभावी ढंग से सीखना मुश्किल हो जाता है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से विज्ञान और गणित जैसे विषयों में योग्य शिक्षकों की कमी होती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

3. कई ग्रामीण परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते, खासकर यदि स्कूल दूर हों, जिससे ड्रॉपआउट दरें अधिक हो सकती हैं।

4. लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव, सामाजिक मानदंड, और पारंपरिक सोच ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा में बाधा बन सकती है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच के कारण डिजिटल विभाजन होता है, जिससे एडटेक समाधानों को अपनाने में बाधा आती है।

ग्रामीण शिक्षा में सुधार के प्रयास–

1. स्कूलों का निर्माण, नवीनीकरण और आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

2. योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना और उनके लिए बेहतर वेतन और सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।

3. गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, जैसे कि छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन योजनाएं, शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है।

4. लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता अभियान चलाना, सामाजिक मानदंडों को बदलना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

5. इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है।

6. ग्रामीण समुदायों को शिक्षा में शामिल करना और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष– ग्रामीण शिक्षा में सुधार एक जटिल चुनौती है, लेकिन यह ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण समुदाय शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक उत्पादक श्रमिक मिलेंगे, जिससे उनकी समग्र आय बढ़ेगी। शिक्षा व्यक्ति की लोगों के समूह का सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाती है क्योंकि यह उन्हें अधिक जानकारी, आत्मविश्वास, कौशल और अनुभव प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का विकास, उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ–साथ अन्य संसाधनों का प्रावधान, शिक्षा में समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग और शिक्षा के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करना ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति को सुधारने के सभी तरीके हैं। एन सभी के साथ ही भारत सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया है जिसका उद्देश्य बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल प्रदान करना है। यह मिशन कक्षा 3 तक बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

पर केंद्रित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया है। मिशन का लक्ष्य हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि "गांव बढ़े, तो देश बढ़े".

संदर्भ सूची –

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2020.
2. NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), NEP 2020 और ग्रामीण विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम की पुनर्रचना, प्रकाशक, NCERT नई दिल्ली, वर्ष 2021
3- **Mehta, Arun C. ,** Impact of NEP 2020 on Rural Education in India, Journal: Educational Perspectives in India, 2021
Tilak, Jandhyala B. G. , Education and Development: Lessons from Indian Experience, Palgrave Macmillan 2020 ISBN: 978-981-13-1370-6
4- **Govinda, R. & Bandyopadhyay, M.,** Access to Elementary Education in India: Analytical Overview, NUEPA (National University of Educational Planning and Administration) 2010, ISBN: 9788175414320
5- **Singh, Avinash,** National Education Policy 2020: A Roadmap for Rural Education Transformation Journal: International Journal of Multidisciplinary Research, 2022, ISSN: 2277-9302
6- **Sharma, Ritu,** Bridging the Digital Divide in Rural India: NEP 2020 and Beyond, Springer 2023 ISBN: 9789819906253